Anusandhanvallari
Vol 2024, No.1
December 2024
ISSN 2229-3388

# भारत की रणनीतिक परिधि में चीन की पैठ: बांग्लादेश के साथ गहरे होते संबंधों का अध्ययन

Pawan Kumar & Shreshtha Sharma

PhD Research Scholar

Centre for South Asian Studies

School of International Studies

Jawaharlal Nehru University

## 1. सारांश

यह लेख भारत, बांग्लादेश और चीन के बीच बदलते भू-राजनीतिक त्रिकोणीय संबंधो का विश्लेषण करता है, जिसमें खासतौर पर चीन और बांग्लादेश के बीच गहराते संबंधों के भारत पर रणनीतिक प्रभाव पर ध्यान दिया गया है। हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी, आज ऐसे अहम भू-क्षेत्र के रूप में उभरा है जहाँ बड़ी शक्तियाँ प्रभाव जमाने की कोशिश में लगी हैं। यह लेख भारत-बांग्लादेश-चीन के संबंधों के इसी बदलते आयाम का विश्लेषण करता है, और यह दिखाता है कि चीन और ढाका के बीच गहराते रिश्ते भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए किस तरह की चुनौती बनते जा रहे हैं।

चीन का दक्षिण एशिया में प्रभाव तेजी से बढ़ा है। बांग्लादेश अब उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है और वहां विदेशी निवेश और बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत कई बुनियादी ढाँचे की परियोजनाएं चल रही है। जैसे पद्मा पुल के ऊपर रेल लाइन और पायरा बंदरगाह। इसके साथ ही चीन बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा रक्षा उपकरण देने वाला देश बन गया है, जो उसकी विदेशी सैन्य खरीद का लगभग 73.6% हिस्सा है। इसमें पनडुब्बियों की आपूर्ति से लेकर संयुक्त सैन्य अभ्यास तक शामिल हैं।

यह बढ़ता हुआ सहयोग भारत के लिए कई स्तरों पर रणनीतिक चुनौतियाँ पैदा करता है। आर्थिक रूप से देखें तो चीन की आधारभूत परियोजनाएं और व्यापार में बदलाव भारत की क्षेत्रीय संपर्क रणनीति और व्यापार प्रभाव को कमजोर कर रहे

हैं। सैन्य दृष्टि से, चीनी हथियारों पर बांग्लादेश की निर्भरता, "डेट ट्रैप डिप्लोमेसी" और "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" जैसी रणनीतियों के साथ मिलकर भारत को घेराव और सिलिगुड़ी कॉरिडोर जैसे संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को लेकर चिंता में डाल रही है।

राजनयिक रूप से भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे है। परंतु 5 अगस्त 2024 की घटना के बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन ने वहा अस्थिरता पैदा की है, जिसने भारत की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। इस अस्थिर राजनीतिक माहौल का लाभ उठाकर चीन भारत के हितों की कीमत पर अपने प्रभाव को और गहरा कर सकता है। बांग्लादेश की हालिया अंतरिम सरकार के तहत विदेश नीति में भारत-समर्थक रुख से हटना नई दिल्ली के लिए एक और चुनौती बन गया है। यह स्पष्ट है कि चीन की रणनीति बहुआयामी जुड़ाव के ज़रिये बांग्लादेश में गहरी पकड़ बनाने की है।

'शक्ति संतुलन सिद्धांत' के आधार पर लेख यह तर्क देता है कि चीन की गतिविधियाँ केवल आर्थिक नहीं हैं, बल्कि भारत के प्रभाव को सीमित करने की एक सुविचारित रणनीति का हिस्सा हैं। निष्कर्षतः भारत के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह इस चुनौती से निपटने के लिए एक मज़बूत और प्रतिस्पर्धी रणनीति बनाए। जिसमें कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तीनों स्तरों पर ठोस प्रयास हों, ताकि भारत अपने पड़ोस में अपनी प्रमुख भूमिका बनाए रख सके और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके।

**कीवर्ड्स :** चीन और बांग्लादेश, भारत का पड़ोस, दक्षिण एशिया, क्षेत्रीय सुरक्षा, चीन का प्रभाव, भारत-चीन संबंध।

## 2. परिचय

बांग्लादेश दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक संरचना में एक केंद्रीय स्थान रखता है। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के संगम पर स्थित, तथा बंगाल की खाड़ी के साथ 710 किलोमीटर लंबी तटरेखा वाला यह देश, उन महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक पहुंच रखता है जो हिंद महासागर को पूर्वी एशिया से जोड़ते हैं। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की निकटता, म्यांमार के साथ साझा सीमाएं, और गहरे समुद्री बंदरगाहों तक संभावित पहुंच, इसके आकार की तुलना में इसे असमान रूप से अधिक रणनीतिक महत्व प्रदान करती है (चौधरी 2023)। 1971 में स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक, भारत ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों के आधार पर बांग्लादेश की रणनीतिक सोच पर प्रभुत्व बनाए रखा (भारद्वाज, बांग्लादेश फॉरेन पालिसी विस्-ए-विस् इंडिया 2003)।

पिछले दो दशकों में, हालांकि, चीन ढाका के बाहरी संबंधों में एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से, बीजिंग ने आधारभूत संरचना, ऊर्जा और औद्योगिक परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। पद्मा ब्रिज रेल लिंक, कर्णफुली नदी टनल और पायरा डीप-सी पोर्ट जैसी प्रमुख परियोजनाएं इस संलग्नता की व्यापकता को दर्शाती है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, रियायती ऋणों का प्रमुख देने वाला है, और इसके लगभग 70 प्रतिशत सैन्य उपकरणों का आपूर्तिकर्ता भी है (सलाम, भुइयां और नीतू 2020)। यह सहयोग सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों तक भी फैला है, जिसमें कन्फ्यूशियस संस्थान, छात्रवृत्तियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

भारत के लिए, चीन की यह गहराती मौजूदगी रणनीतिक घेरेबंदी की चिंताओं को जन्म देती है, जिसे भारतीय रणनीतिक विमर्श में अक्सर बीजिंग की "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" रणनीति का हिस्सा माना जाता है (चौधरी 2023)। तीस्ता नदी जल बंटवारे के विवाद जैसे अनसुलझे द्विपक्षीय मुद्दों ने ढाका में भारत के घटते प्रभाव की धारणा को और मजबूत किया है। 5 अगस्त 2024 की राजनीतिक घटनाएं, विवादित चुनाव और घरेलू अशांति ने नई दिल्ली की सहभागिता रणनीति को और जटिल बना दिया है। मौजूदा स्थिति में, बांग्लादेश "रणनीतिक संतुलन" की नीति अपनाता हुआ प्रतीत होता है, जिससे वह भारत और चीन दोनों से आर्थिक और कूटनीतिक लाभ अधिकतम करना चाहता है, बिना किसी एक के प्रति विशेष रूप से झुकाव दिखाए (भारद्वाज, टेनेंट्स ऑफ़ इंडिया-बांग्लादेश रिलेशन्स 2020)।

दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती आक्रामकता को पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के साथ उसके समानांतर जुड़ाव के व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जो आर्थिक और सुरक्षा साझेदारियों का ऐसा नेटवर्क बनाता है जो भारत की पारंपरिक क्षेत्रीय प्रधानता को चुनौती देता है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण आर्थिक कूटनीति, सैन्य सहयोग और सॉफ्ट पावर साधनों को शामिल करते हुए, भारत की बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा, BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय संगठनों में प्रभाव, और उसकी इंडो-पैसिफिक रणनीति को प्रभावित करता है।

इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि चीन बांग्लादेश के साथ आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक क्षेत्रों में किस प्रकार और कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। साथ ही, यह अध्ययन इस बात का भी आकलन करता है कि चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ते इस जुड़ाव का भारत की सुरक्षा, उसकी विदेश नीति और दक्षिण एशिया में उसके क्षेत्रीय प्रभाव पर क्या असर पड़ रहा है।

इस शोध में तीन प्रमुख प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला, पिछले एक दशक में चीन और बांग्लादेश के रिश्तों में क्या बदलाव आए हैं और वे कैसे आगे बढ़े हैं। दूसरा, इन रिश्तों का दक्षिण एशिया में भारत के रणनीतिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तीसरा, भारत को अपने रणनीतिक हित सुरक्षित रखने के लिए बांग्लादेश के प्रति अपनी नीति में किन बदलावों की आवश्यकता है।

इस शोधपत्र की कार्यप्रणाली गुणात्मक और विश्लेषणात्मक विधि पर आधारित होगी, जिसमें प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अकादमिक जर्नलों और पुस्तकों की समीक्षा शामिल होगी। इसके अतिरिक्त, भारत, चीन और बांग्लादेश तीनों देशों के आधिकारिक बयानों और नीतियों की समीक्षा भी की जाएगी, ताकि विषय पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके। विश्लेषण में सरकारी आँकड़े, दोनों देशों के बीच हुए समझौते और विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा किए गए शोधों को मिलाकर एक ऐसा मूल्यांकन तैयार किया गया है जो तथ्यात्मक और अकादमिक दृष्टि से मजबूत हो।

संक्षेप में, यह शोधपत्र बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में भारत और चीन की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र में रखकर इस बात की गहन जांच का आधार तैयार करती है कि ढाका में बीजिंग की गहराती मौजूदगी नई दिल्ली की दीर्घकालिक सुरक्षा और कूटनीतिक रुख को कैसे प्रभावित करती है।

## 3. बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिति और विदेश नीति की दिशा

बांग्लादेश दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के रणनीतिक संगम पर स्थित है, जिसकी समुद्री तटरेखा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है और सीमाएँ भारत तथा म्यांमार दोनों से मिलती हैं। इसका भौगोलिक स्थान इसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के केंद्र में रखता है, जिससे यह उन अहम समुद्री गलियारों पर प्रभाव डाल सकता है जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार और सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। बंगाल की खाड़ी न केवल एक वाणिज्यिक मार्ग के रूप में कार्य करती है, बल्कि अब क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का केंद्र भी बन रही है, जिससे बांग्लादेश का भू-राजनीतिक महत्व उसके आकार से कहीं अधिक बढ़ जाता है (करीम 2023)।

भारत के साथ ऐतिहासिक तालमेल ने लंबे समय तक बांग्लादेश की विदेश नीति को परिभाषित किया है। स्वतंत्रता के बाद से, ढाका ने सुरक्षा गारंटी और आर्थिक संबंधों के लिए भारत पर भरोसा किया, जिससे राजनीतिक एकजुटता और भौगोलिक आवश्यकता पर आधारित एक सौहार्दपूर्ण संबंध कायम हुआ (भारद्वाज, बांग्लादेश फॉरेन पालिसी विस्-ए-विस् इंडिया 2003)। हालांकि, घरेलू राजनीति ने अक्सर बांग्लादेश के विदेश नीति रुख को प्रभावित

किया है। सत्ता में बदलाव–खासकर अवामी लीग और उसके प्रतिद्वंद्वियों के बीच–नई दिल्ली के प्रति दृष्टिकोण में बड़े अंतर लाए हैं। आंतरिक राजनीतिक सहमति की कमी के कारण, बांग्लादेश की विदेश नीति अक्सर दलगत विचारों से संचालित होती है, जो कभी-कभी भारत के कूटनीतिक प्रयासों से स्वतंत्र होती है (कुमार 2014)।

वर्तमान में, बांग्लादेश "रणनीतिक संतुलन" की विदेश नीति अपना रहा है। यह भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध बनाए रखते हुए, बीजिंग, टोक्यो और अन्य बाहरी शक्तियों से भी संबंध विकसित कर रहा है ताकि अपने साझेदारों का दायरा विविध बनाया जा सके। यह सोच-समझकर अपनाया गया संतुलन अवसर और आवश्यकता, दोनों का परिणाम है, घरेलू आर्थिक प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय दबावों के कारण ढाका कई देशों से जुड़ाव बनाए रखता है, ताकि किसी एक साझेदार पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके (हसन 2024)।

आर्थिक दृष्टि से, बांग्लादेश ने हमेशा विविध अवसंरचना निवेश और वैश्विक एकीकरण के माध्यम से विकास को प्राथमिकता दी है। यह भारत प्रेरित बीबीआईएन (बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल) जैसे क्षेत्रीय गलियारों से लेकर बेल्ट एंड रोड पहल के तहत चीनी परियोजनाओं तक, विभिन्न विकास साझेदारियों की तलाश करता है। इसी बीच, अपनी “लुक ईस्ट” नीति के तहत, बांग्लादेश ने जापान और थाईलैंड जैसे देशों के साथ व्यापार, निवेश और अवसंरचना संपर्क को बढ़ाया है (प्लाजमानन 2022)।

घरेलू राजनीति भी विदेश नीति के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। अवामी लीग, जो धर्मनिरपेक्ष और भारत समर्थक रुख वाली है, आम तौर पर नई दिल्ली के साथ गहरे सहयोग का पक्ष लेती है। इसके विपरीत, विपक्षी दल समय-समय पर भारत-विरोधी भावनाओं को भुनाते हैं और संप्रभुता के मुद्दों को उठाकर चीन या अन्य बाहरी शक्तियों के साथ अधिक जुड़ाव को उचित ठहराते हैं (पट्टनायक 2005)। यह उतार-चढ़ाव रणनीतिक अनिश्चितता को मजबूत करता है और भारत के लिए सतर्क और लचीला बने रहने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

संस्थागत स्तर पर, बांग्लादेश ने अपनी व्यापक रणनीतिक दृष्टि के अनुरूप समुद्री आधारभूत संरचना को मजबूत करने और आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मातरबारी और पायरा गहरे समुद्री बंदरगाहों के विकास जैसी पहलें देश को एक क्षेत्रीय समुद्री केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे व्यापार क्षमता में वृद्धि हो और इंडो-पैसिफिक के प्रमुख मार्गों से जुड़ाव बेहतर हो सके। यह आधारभूत संरचना पर जोर देने वाली पहल बांग्लादेश की “इंडो-पैसिफिक आउटलुक” में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुरूप है, जो समुद्री सुरक्षा, सतत संपर्क और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान पर जोर देती है (मिनिस्ट्री ऑफ़ इनफार्मेशन

एंड ब्राडकास्टिंग 2023)। विश्लेषकों का मानना है कि यह दृष्टिकोण इंडो-पैसिफिक की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें बांग्लादेश अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए क्षेत्रीय शक्तियों और बहुपक्षीय मंचों के साथ संतुलित साझेदारी बनाए रख रहा है (सैमुम 2023)।

## 4. बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी

### 4.1 आर्थिक निवेश और व्यापार

बांग्लादेश में चीन की आर्थिक भूमिका बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना परियोजनाओं के माध्यम से उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की रणनीतियों से सीधे जुड़ी हैं। पद्मा ब्रिज रेल लिंक इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। यह लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर की परियोजना है, जिसे चीन के एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक के सह-वित्त पोषण से विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ढाका और जशोर को बेहतर रेल लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ना है (सज्जाद, और अन्य 2024)। यह परियोजना क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने और दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश के जिलों में आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

इसी क्रम में, चट्टोग्राम में कर्णफुली टनल, जिसका वित्तपोषण और क्रियान्वयन चीनी कंपनियों द्वारा किया गया है। इन निवेशों की तकनीकी गहराई का प्रतीक है। यह बंदरगाह-शहर कनेक्टिविटी को मजबूत करता है और चीन को एक अपरिहार्य अवसंरचना साझेदार के रूप में स्थापित करता है।

पायरा डीप सी पोर्ट, जिसे चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ हुए समझौतों के तहत विकसित किया जा रहा है, बांग्लादेश के लिए चीन की एक प्रमुख रणनीतिक अवसंरचना पहल है। 11 से 15 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच अनुमानित निवेश के साथ, यह परियोजना दिखाती है कि किस तरह बीआरआई से जुड़ी चीन की योजनाएं बांग्लादेश की लॉजिस्टिक क्षमता को मजबूत कर रही हैं और उसे चीन केंद्रित समुद्री और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क में और गहराई से जोड़ रही हैं ।

इसके अलावा, अवसंरचना, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्रों में चीन की आर्थिक सॉफ्ट पावर बांग्लादेश के विकास पथ को नए सिरे से आकार दे रही है (आलोम, होसेन और सलम 2024)। कुल मिलाकर, ये पहल चीन की बहुआयामी वाणिज्यिक भागीदारी के माध्यम से रणनीतिक प्रभाव को गहरा करने की मंशा को दर्शाती हैं।

### 4.2 रक्षा और रणनीतिक सहयोग

रणनीतिक मोर्चे पर, बांग्लादेश ने चीन से दो टाइप 035जी (मिंग क्लास) पनडुब्बियां खरीदीं, जिनकी कीमत लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई जाती है। यह सौदा 2013 में अंतिम रूप से तय हुआ और 2016 में डिलीवरी पूरी हुई। यह समझौता ढाका की नौसैनिक आधुनिकीकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है (सूरी 2016)। यह अधिग्रहण दोनों सरकारों के बीच रक्षा सहयोग की रणनीतिक गहराई को रेखांकित करता है। विश्लेषण से पता चलता है कि 2010 के बाद से बांग्लादेश के दो-तिहाई से अधिक हथियार आयात चीन से हुए हैं, जिससे बीजिंग बांग्लादेश के लिए सैन्य उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है। हथियारों के अलावा, सैन्य से सैन्य संपर्क, जैसे अधिकारियों का प्रशिक्षण और रणनीतिक वार्ता ने इस साझेदारी को और मजबूत किया है (फुनेओले, और अन्य 2023 )।

ये रक्षा सहयोग बांग्लादेश की सुरक्षा क्षमताओं को सीधे तौर पर मजबूत करते हैं और इंडो-पैसिफिक में शक्ति प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में चीन की क्षेत्रीय सैन्य उपस्थिति को भी सुदृढ़ करते हैं।

### 4.3 कुटनीतिक और सॉफ्ट पॉवर का जुडाव

आधारभूत संरचना और रक्षा के अलावा, चीन दीर्घकालिक धारणा और प्रभाव बनाने के लिए सॉफ्ट पावर और कूटनीति का उपयोग करता है। शैक्षणिक विश्लेषण के अनुसार, इसमें बहुआयामी रणनीति शामिल है। भाषा संस्थान, छात्रवृत्तियां और सांस्कृतिक साझेदारियां, जो स्थायी सद्भावना को बढ़ावा देती हैं (आलोम, होसेन और सलम 2024)।

जनस्वास्थ्य भी सॉफ्ट पावर का एक माध्यम रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान चीन ने बांग्लादेश को वैक्सीन और स्वास्थ्य सहायता दी। यह मदद सरकारी स्तर पर लागू हुई, लेकिन इससे बीजिंग की छवि एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में मजबूत हुई।

इसके अलावा, उच्च-स्तरीय कूटनीतिक मुलाकातें और द्विपक्षीय ढांचे इन ठोस निवेशों के साथ जुड़े हुए हैं। ढाका-बीजिंग संबंधों के सहकर्मी समीक्षित अध्ययनों के अनुसार, सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य कूटनीति अवसंरचना और रणनीतिक सहयोग के इस मिश्रण को मजबूत करती है, जिससे साझेदारी कई स्तरों पर गहराती है (सलाम, भुइयां और नीतू 2020)।

इस प्रकार, चीन की सॉफ्ट पावर रणनीतियां सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य कूटनीति, न केवल उसके कठोर आधारभूत संरचना निवेशों को पूरक करती हैं, बल्कि बांग्लादेश के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक सामंजस्य को भी मजबूत करती हैं।

## 5. भारत की रणनीतिक चिंताएँ और प्रतिक्रियाएँ

### 5.1 रणनीतिक क्षेत्र में कथित कमी

भारत लंबे समय से बांग्लादेश को अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने और बंगाल की खाड़ी में एक बफर के रूप में देखता आया है। हालांकि, बांग्लादेश में चीन की बढ़ती बुनियादी ढांचा उपस्थिति ने नई दिल्ली में यह चिंता बढ़ा दी है कि धीरे-धीरे ढाका की निर्भरता भारत से हटकर चीन पर बढ़ रही है। यह चिंता व्यापक "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" सिद्धांत से जुड़ी है, जिसके तहत दक्षिण एशिया में चीनी वित्तपोषित बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे को भारत को घेरने की रणनीति के रूप में देखा जाता है (खुराना 2008)।

दोनों देशों के बीच एक प्रमुख विवादास्पद मुद्दा तीस्ता नदी विवाद है, जहां जल बंटवारे की व्यवस्था भारत के अंदरूनी राजनीतिक विरोध, विशेषकर पश्चिम बंगाल से, के कारण अटकी हुई है (उप्रेती और सलमान 2011)। बाध्यकारी समझौते की कमी ने चीन को बांग्लादेश में जल परियोजनाओं के विकास में मदद की पेशकश का अवसर दिया है, जिससे भारत की रणनीतिक गणनाएँ और जटिल हो गई हैं।

### 5.2 जुड़ाव का तुलनात्मक विश्लेषण

भारत का बांग्लादेश के साथ विकास सहयोग मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के आर्थिक संबंध प्रभाग (ERD) के माध्यम से दी जाने वाली ऋण रेखाओं (LoCs) पर आधारित है। अगस्त 2024 तक, भारत ने 7.862 अरब अमेरिकी डॉलर की ऋण रेखाएँ दी थीं (व. भारत सरकार 2024), जिससे वह ऋण मात्रा के हिसाब से भारत सबसे बड़ा विकास भागीदार बन गया। ये ऋण रेखाएँ मुख्य रूप से कनेक्टिविटी, ऊर्जा और रक्षा-संबंधी बुनियादी ढांचे पर केंद्रित हैं।

हालांकि, परियोजनाओं में देरी और नौकरशाही अड़चनों ने भारतीय परियोजनाओं की कार्यक्षमता को कम कर दिया है। भारत की ऋण रेखाओं की शर्तो और लम्बी प्रक्रियाओ ने परियोजना को पूरा करने की गति को धीमा किया है, जबकि चीन की तेज़ व्यावसायिक बुनियादी ढांचा पहल अक्सर लंबी स्वीकृति प्रक्रियाओं को दरकिनार कर देती है (इस्लाम 2023)।

जहां भारत सांस्कृतिक संबंधों, सीमा बुनियादी ढांचा सुधार और क्षमता-विकास कार्यक्रमों पर जोर देता है, वहीं चीन का दृष्टिकोण बड़े पैमाने के बंदरगाह, पावर प्लांट और औद्योगिक क्षेत्रों पर अधिक केंद्रित है, जिससे उसे अधिक स्पष्ट आर्थिक प्रभाव मिलता है।

**5.3 भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक समायोजन**

इसके जवाब में, भारत ने त्रिपक्षीय ढांचों का विस्तार करने की कोशिश की है, जैसे भारत-जापान-बांग्लादेश कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जिसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी में बंदरगाह और परिवहन संपर्कों को मजबूत करना है (बनर्जी और बासु 2021 )।

समुद्री सहयोग भी तेज हुआ है। रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास और समन्वित गश्तें हुई हैं, जिनका उद्देश्य समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना और बाहरी क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करना है (र. भारत सरकार 2023)।

इसके अलावा, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और रक्षा वार्ताएं भी मजबूत हुई हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2023 में ढाका में हुई 5वीं वार्षिक भारत-बांग्लादेश रक्षा वार्ता में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई, जिसमें संयुक्त अभ्यास बढ़ाना और सैन्य प्रशिक्षण को अधिक जटिल बनाना शामिल है (रक्षा मंत्रालय 2023)।

## 6. क्षेत्रीय संदर्भ: दक्षिण एशिया का बदलता रणनीतिक परिदृश्य

बांग्लादेश दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक रणनीतिक स्थान रखता है, और उसका इंडो-पैसिफिक आउटलुक मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित बंगाल की खाड़ी पर जोर देता है–जिसे किसी भू-राजनीतिक गुट से जोड़ने के बजाय विकास-केन्द्रित रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह ढाका को भारत, जापान, चीन और आसियान के साथ सहज रूप से जुड़ने में सक्षम बनाता है, जिससे उसकी रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ती है (ब. अहमद 2023)। संस्थागत स्तर पर, बांग्लादेश BIMSTEC और SAARC जैसे क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से अपनी भूमिका को मजबूत करता है। 20 मई 2024 को लागू हुआ औपचारिक BIMSTEC चार्टर ढाका की व्यापार, परिवहन और प्रौद्योगिकी में व्यापक सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो दक्षिण एशिया में संपर्क बढ़ाने की दिशा में उसकी केंद्रीय भूमिका को स्थापित करता है। इसी तरह, 1985 में हस्ताक्षरित SAARC चार्टर अब भी क्षेत्रीय

कूटनीति के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, जो दक्षिण एशिया में बहुपक्षवाद के प्रति बांग्लादेश की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है (सेक्रेटेरिएट 2022)।

क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति बांग्लादेश की अपनी रणनीतिक स्थिति को और गहराई देती है। नेपाल, जो ऐतिहासिक रूप से भारत का सहयोगी रहा है, ने बुनियादी ढांचे में विविधता लाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपनाया है। बीआरआई के 2015 के बाद के चरण में उसका संवैधानिक और भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण, संप्रभु विकास स्वायत्तता की उसकी कोशिश को दर्शाता है (पौडेल 2021)। श्रीलंका में, कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट चीन के समुद्री प्रभाव का एक बड़ा प्रतीक है, जिसमें चीनी कंपनियों के माध्यम से पुनर्निर्मित शहरी आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है, जो कोलंबो के शहरी और लॉजिस्टिक परिदृश्य को नया रूप दे रहा है ।

भारत, इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) जैसे क्षेत्रीय ढाँचों के माध्यम से जवाब बनाता है, जो खुले समुद्र, सतत विकास और समावेशी समुद्री शासन को बढ़ावा देता है। विद्वानों के विश्लेषण में IPOI को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक रणनीतिक विकल्प के रूप में वर्णित किया गया है, जो क्वाड और अन्य बहुपक्षीय मंचों में भारत की बढ़ती साझेदारियों के साथ मेल खाता है (उपाध्याय 2021)।

आर्थिक सहयोग भी दक्षिण एशिया की रणनीतिक गतिशीलता को आकार दे रहा है। क्वाड की सप्लाई चेन रेज़िलिएंस इनिशिएटिव (SCRI) का उद्देश्य उत्पादन और आपूर्तिकर्ता नेटवर्क को किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से दूर विविध बनाना है। इसे इंडो-पैसिफिक में आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के एक माध्यम के रूप में सराहा गया है (कर्टिस 2023)।

उप-क्षेत्रीय स्तर पर, बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच माल और यात्रियों के निर्बाध स्थलीय परिवहन को सक्षम बनाता है, जिससे व्यापार लागत कम होती है और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी बढ़ती है। यह बांग्लादेश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय बंदरगाहों और बाजारों के साथ अपने एकीकरण को मजबूत करता है (मतिअस , लेब्रैंड और पेटन 2021)। बांग्लादेश के लिए रणनीतिक अवसर बिम्सटेक आधारित कनेक्टिविटी, भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव और क्वाड से जुड़े ढांचे को चुनिंदा चीनी अवसंरचना वित्तपोषण के साथ संतुलित करने में है, ताकि वित्तीय स्थिरता और रणनीतिक स्वायत्तता बनी रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा समुद्री प्रतिस्पर्धा अब भौतिक ठिकानों से अधिक लॉजिस्टिक्स, नियामक प्रभाव और मानक नेतृत्व पर केंद्रित है। इस कारण, बिम्सटेक

और बीबीआईएन जैसे बहुपक्षीय तंत्रों तक पहुंच ढाका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है (मेगल और मिर्ज़ा 2022)।

संक्षेप में, बांग्लादेश इस पूरे क्षेत्रीय ढांचे का अहम हिस्सा है। वह बहुपक्षीय सहयोग और इंडो-पैसिफिक से जुड़ाव के जरिए अपनी भूमिका बढ़ा रहा है, वहीं चीन से उसके रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। भारत के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह बीबीआईएन, बिम्सटेक और व्यापार सहयोग के जरिए बांग्लादेश का साथ दे। इससे बंगाल की खाड़ी खुली रहेगी और बांग्लादेश को किसी एक पक्ष को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

## 7. भारत के लिए नीतिगत निहितार्थ

भारत का बांग्लादेश के साथ रणनीतिक जुड़ाव एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ उसे प्रभाव बनाए रखते हुए ढाका की संप्रभुता का सम्मान करने वाली व्यापक और लचीली नीति की आवश्यकता है। सबसे पहले, भारत को अधिक उत्तरदायी और सम्मानजनक द्विपक्षीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। विद्वानों के अध्ययन बताते हैं कि भारत की भागीदारी तब सबसे प्रभावी होती है जब यह बांग्लादेश की प्राथमिकताओं के अनुरूप होती है, जैसे व्यापार को बढ़ावा देना, संपर्क (कनेक्टिविटी) को सुदृढ़ करना और जन-केंद्रित पहलों को प्रोत्साहित करना। ना कि ऊपर से थोपी गई शर्तों वाले सहयोग के माध्यम से (अहमद और शहरयार 2024)। ऐसा संबंध, जो बांग्लादेश की विकासात्मक एजेंडा को समझे और उसके अनुसार ढले, सद्भावना और विश्वास का निर्माण करेगा।

दूसरा, भारत को अपनी परियोजनाओं की कार्यान्वयन गति और पारदर्शिता में सुधार करना होगा। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन की एक केस स्टडी में बताया गया है कि शर्तें, विशेष रूप से बंधी हुई खरीद, जिसमें भारतीय ठेकेदारों और सामग्री के उपयोग को अनिवार्य किया जाता है, ने बांग्लादेश में लाइन ऑफ क्रेडिट के कार्यान्वयन को काफी धीमा कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय लाभ और दक्षता दोनों कम हो गए (गैलेक्सी 2019)। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि खरीद संबंधी प्रतिबंधों को कम किया जाए, स्थानीय हितधारकों को शामिल किया जाए, और निगरानी क्षमता को मजबूत किया जाए, ताकि परियोजनाओं के परिणाम बेहतर हो सकें।

तीसरा, समुद्री और साइबर सुरक्षा सहयोग भारत और बांग्लादेश के लिए भरोसा बनाने और बंगाल की खाड़ी के समुद्री मार्गों की सुरक्षा करने का एक व्यावहारिक तरीका है। क्षेत्र-आधारित अध्ययनों में साझा मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, सूचना-संलयन तंत्र, राडार और एआईएस नेटवर्क, और तटीय देशों के बीच नियमित समन्वित गश्त

की सिफारिश की गई है, ताकि पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरह के खतरों को संभाला जा सके (राजू 2018)।

डिजिटल क्षेत्र में, संयुक्त प्रशिक्षण और प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्थाएँ बांग्लादेश और भारत की मौजूदा नीतियों के ऊपर विकसित की जा सकती हैं। भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 एक आधार प्रदान करती है, जिससे दोनों देश आपसी कार्यसमूहों और अभ्यासों के ज़रिए घटनाओं पर प्रतिक्रिया, क्षमता निर्माण और सूचना साझाकरण जैसे उपायों को लागू कर सकते हैं (इ. भारत सरकार 2013 )।

इन सभी कदमों को मिलाकर देखा जाए तो वे समुद्र में निरोधक क्षमता और ऑनलाइन लचीलापन दोनों को मजबूत करते हैं, जबकि सहयोग को बांग्लादेश की प्राथमिकताओं और भारत की सुरक्षा हितों के अनुरूप रखते हैं (मजूमदार 2023)।

चौथा, भारत को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में विश्वसनीय आर्थिक पहल तैयार करनी चाहिए। इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकॉनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) एक बहु-क्षेत्रीय रणनीतिक परियोजना है, जिसमें परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल है। यह एक सतत और पारदर्शी विकल्प के रूप में सामने आता है। यूरोपीय संघ के सुरक्षा अध्ययन संस्थान (EUISS) के एक प्रामाणिक विश्लेषण के अनुसार, IMEC में व्यापार मार्गों में विविधता लाने, ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने और आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन बढ़ाने की बड़ी क्षमता है (घनेम और कासिएदो 2024)।

इसके अतिरिक्त, बहुपक्षीय ढाँचे जैसे बिम्सटेक और बीबीआईएन क्षेत्रीय स्वामित्व पर आधारित रणनीतिक अवसर प्रदान करते हैं। बिम्सटेक चार्टर, जिसे भारत, बांग्लादेश और अन्य सदस्य देशों ने स्वीकार किया है, साझा मानदंडों और सहयोगी अवसंरचना योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह बांग्लादेश की बहुपक्षवाद की इच्छा के अनुरूप एक उपयुक्त मंच बनाता है (चार्टर 2022)। उप-क्षेत्रीय स्तर पर, बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते परिवहन में देरी और लागत को कम करते हैं, जिससे बांग्लादेश के व्यापारिक मार्गों को भारतीय बंदरगाहों और उससे आगे तक अधिक सहज और सस्ता बनाया जा सकता है।

भारत को चाहिए कि वह परियोजनाओं के कामकाज और आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए संस्थागत कदम उठाए। इसके लिए एक बांग्लादेश पर खास ध्यान देने वाली टास्क फोर्स और एक संयुक्त भारत-

बांग्लादेश इंफ्रास्ट्रक्चर परिषद बनाई जा सकती है। ये संस्थाएं मिलकर योजना बनाने, खरीद की प्रक्रिया को आसान करने और काम की निगरानी करने का जिम्मा लेंगी।

दुनिया के अनुभव बताते हैं कि जब ऐसे विशेष तंत्र बनाए जाते हैं, तो परियोजनाओं में देरी और खर्च बढ़ने की समस्या काफी कम हो जाती है। वजह यह है कि इससे जिम्मेदारियां साफ हो जाती हैं, खरीद की प्रक्रिया एक जैसी हो जाती है और गुणवत्ता की जांच व परियोजना की तैयारी अच्छे से हो पाती है (वर्ल्ड 2014)।

अंततः, भारत की बांग्लादेश-नीति में सुधार ऐसा होना चाहिए जिसमें सार्वभौमिकता का सम्मान, लचीली परियोजना व्यवस्था, साझी सुरक्षा सहयोग, और बहुपक्षीय आर्थिक विकल्प शामिल हों। इस संतुलित और सहयोगात्मक रास्ते से भारत केवल एक अनिवार्य पड़ोसी ही नहीं, बल्कि एक इच्छुक और भरोसेमंद साझेदार के रूप में भी सामने आएगा। इससे भारत अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित कर सकेगा और साथ ही बांग्लादेश की स्वतंत्र भूमिका तथा क्षेत्रीय जुड़ाव को मज़बूत करेगा।

## 8. निष्कर्ष

यह अध्ययन दर्शाता है कि बांग्लादेश के साथ चीन की भागीदारी अब बहुआयामी हो चुकी है। यह केवल अवसंरचना और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा सहयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और राजनीतिक प्रतीकवाद तक फैल गई है। विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक परिदृश्य में चीन की उपस्थिति को और गहरा किया है। ये संबंध ढाका को संपर्क और औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन साथ ही ऐसी जटिल निर्भरताएँ भी पैदा करते हैं जिन्हें सावधानी से संभालना होगा।

भारत के लिए, चीन-बांग्लादेश संबंधों का विस्तार एक रणनीतिक चुनौती है, लेकिन यह नई दिल्ली के प्रभाव को मूल रूप से कमजोर नहीं करता। भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक समानता और विकासात्मक परस्पर निर्भरता भारत के प्रमुख लाभ बने हुए हैं। बिम्सटेक, बीबीआईएन और इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव जैसी परियोजनाएँ दिखाती हैं कि भारत बीआरआई के विकल्प के रूप में सहयोगात्मक और पारदर्शी मार्ग प्रस्तुत करना चाहता है। हालांकि, इन पहलों को प्रभावी बनाने के लिए अधिक दक्षता, समयबद्धता और निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है, ताकि बांग्लादेश को अपने विकास लक्ष्यों के अनुरूप ठोस लाभ मिल सकें।

विश्लेषण यह भी स्पष्ट करता है कि भारत के रणनीतिक हित चीन से टकराव के बजाय सक्रिय कूटनीति और प्रतिस्पर्धी आर्थिक भागीदारी से बेहतर सुरक्षित हो सकते हैं। तेज़ परियोजना क्रियान्वयन, स्पष्ट संचार और वास्तविक साझेदारी भारत की विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश की समान चुनौतियाँ और अवसर हैं। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) जैसी आर्थिक पहल भारत की दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता और संपर्क में निवेश की प्रतिबद्धता को और मज़बूत संकेत दे सकती है।

महत्वपूर्ण यह भी है कि बांग्लादेश की स्वायत्त भूमिका को कम करके नहीं आँका जाना चाहिए। ढाका की विदेश नीति अब रणनीतिक संतुलन से पहचानी जाती है, जहाँ वह भारत और चीन दोनों के साथ साझेदारी का उपयोग अपने विकास और सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने में करता है। भारत के लिए, इस एजेंसी को स्वीकारना और सम्मान देना ज़रूरी है। कठोर दबाव या चीन-विरोधी रुख की अपेक्षा बांग्लादेश को दूर कर सकती है, जबकि संतुलित और सम्मानजनक जुड़ाव भरोसा मज़बूत करेगा।

अंततः, चीन की बढ़ती भूमिका के बीच भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा बाहरी प्रतिस्पर्धा से कम और भारत की नेतृत्व क्षमता पर अधिक निर्भर करेगी। कूटनीति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और बांग्लादेश की प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशीलता को जोड़कर, भारत बंगाल की खाड़ी में अपने रणनीतिक हित सुरक्षित रख सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता व समावेशी व्यवस्था में योगदान दे सकता है।

References

1. अहमद, फरहाद, and सालेह शहरयार. "बांग्लादेश–इंडिया बॉर्डर हाटस: इश्यूज चैलेंजेज एंड ओप्पोर्तुनिटीज़." *बांग्लादेश इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज जर्नल* 45, no. 2 (2024): 221-258.
2. अहमद, बशीर. "द इम्प्लीकेशन ऑफ़ इंडो-पसफिक स्ट्रेटेजिइस फॉर बांग्लादेश चैलेंजेस एंड ऑप्शनस." *एशियाई स्टडीज जर्नल जहाँगीरनगर यूनिवर्सिटी* 42 (2023): 1-16.
3. आलोम, मोहम्मद शम्सुल, मोहम्मद खलील होसेन, and एल्फतिः अब्दुल्लाह अब्दुस सलम. "चाइना.स कल्चरल सॉफ्ट पॉवर इन बांग्लादेश: अचिएवेमेन्त्स एंड चैलेंजस ( 2000-2020 )." *जर्नल ऑफ़ एशियाई एंड अफ्रीकन सोशल साइंस एंड हमनीटीएस* 10, no. 1 (2024): 29-45.
4. इस्लाम, एम्. "टाईड ऐड एंड डेवलपमेंट इन साउथ एशिया: स्ट्रक्चरल बोतलनेक्स इन इंडिया–बांग्लादेश लाइन्स ऑफ़ क्रेडिट." *साउथ एशिया इकनोमिक जर्नल* 24, no. 1 (2023): 45-60.

5. उपाध्याय, शिशिर. "इंडो-पसिफ़िक ओसियन इनिशिएटिव एन ओप्पोरचुनिटी टू क्रिएट न्यू इंस्टीटूशन्स फॉर मेरीटाइम गवर्नेंस." *ऑस्ट्रेलियाई जर्नल ऑफ़ मेरीटाइम ओसियन अफेयर्स* (टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन) 15, no. 1 (2021): 1-11 .

6. उप्रेती, किशोर, and सलमान एम् ए सलमान. "लीगल आस्पेक्ट्स ऑफ़ शेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ़ ट्रांसबाउन्डरी वाटर्स इन साउथ एशिया: प्रेवेंटिंग कन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोटिंग कोऑपरेशन." *हयड्रोलॉजिकल साइंसेज जर्नल* (टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन ) 56, no. 4 (2011): 641-661.

7. करीम, तारिक. "इंस्टिट्यूट ऑफ़ साउथ एशियन स्टडीज." *नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर.* 2023. https://www.isas.nus.edu.sg/papers/connectivity-and-cooperation-the-bay-of-bengal-and-bangladesh-in-the-indo-pacific-region/.

8. कर्टिस , लिसा. "द क्वाड'स रोल इन शिफ्टिंग टू रेसिलिएंट टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी." *सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्यूरिटी.* दिसम्बर 13, 2023. https://www.cnas.org/publications/commentary/the-quads-role-in-shifting-to-resilient-technology-supply-chains-and-energy-security.

9. कुमार, आनंद. "डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ़ बांग्लादेश एंड इंडिया–बांग्लादेश रिलेशन्स." *स्ट्रेटेजिक एनालिसिस* (टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन ) 38, no. 5 (2014): 652-667.

10. खुराना, गुरप्रीत एस. "चीन'स 'स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स' इन द इंडियन ओसियन एंड इट्स सिक्योरिटी इम्प्लिकेशन्स." *स्ट्रेटेजिक एनालिसिस* (टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन) 32, no. 1 (2008): 1-39.

11. गैलेक्सी, साउथ साउथ. "साउथ-साउथ आइडियाज: हाउ कोहेरेंट आर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीस ऑफ़ द साउथर्न फाइनेंस प्रोवाइडर्स? ए केस स्टडी ऑफ़ इंडो-बांग्लादेश लाइन्स ऑफ़ क्रेडिट." *यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ-साउथ कोऑपरेशन.* मार्च 18, 2019. https://southsouth-galaxy.org/south-south-global-thinkers/how-coherent-are-trade-and-investment-policies-of-the-southern-finance-providers/.

12. घनेम, डालिए, and अमिया सांचेज़ कासिएदो . "फ्रॉम हाइप टू होराइजन: व्हाट द ई यू नीड्स टू नो टू ब्रिंग आईएम्ईसी टू लाइफ." *यूरोपियन यूनियन इंस्टिट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज.* जून 2024. https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_2024-10_IMEC.pdf.

13. चार्टर, बिम्सटेक. "बिम्सटेक चार्टर प्रीअम्बल ." *विदेश मंत्रालय भारत सरकार* . 2022. https://www.mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/022M3847.pdf.

14. चौधरी, राहुल नाथ. "चीन इन बांग्लादेश: डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और दीपेनिंग इन्फ्लुएंस." In *मैपिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन साउथ एशिया*, by राहुल नाथ चौधरी, 65-93. सिंगापूर : पलग्रैवे मैमिलन सिंगापुर, 2023.

15. पट्टनायक, स्मृति एस. "इंटरनल पोलिटिकल डायनामिक्स एंड बांग्लादेश'स फॉरेन पालिसी टुवर्ड्स इंडिया." *स्ट्रेटेजिक एनालिसिस* (टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन ) 29, no. 3 (2005): 395-426.

16. पौडेल, दिनेश . "हिमालयन बीआरआई : एन इंफ्रास्ट्रक्टरल कन्जंक्टरे एंड शिफ्टिंग डेवलपमेंट इन नेपाल." *एरिया डेवलपमेंट एंड पालिसी* (टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन ) 7, no. 1 (2021): 1-21 .

17. प्लाजमानन, जोहानस. "स्माल स्टेट्स एंड कंपेटिंग कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजीज: व्हाट एक्सप्लाइन्स बांग्लादेश'स सक्सेस इन रिलेशन्स विथ एशिया'स मेजर पावर्स?" *द पसिफ़िक रिव्यु* (टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन ) 35, no. 4 (2022): 736-764.

18. फुनेओले, मैथ्यू पी, ब्रायन हार्ट, ईडन पावर्स रिग्गस , and जेनिफर जून. "सबमरीन डिप्लोमेसी ए स्नैपशॉट ऑफ़ चीन'स इन्फ्लुएंस अलोंग द बे ऑफ़ बंगाल." *सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज.* नवम्बर 2023 . https://features.csis.org/snapshots/china-submarine-diplomacy/.

19. बनर्जी , श्रीपर्णा, and प्रत्नाश्री बासु. "ओआरऍफ़ इशू ब्रीफ 460." *ओआरऍफ़* . 2021 . https://www.orfonline.org/research/india-japan-partnership-in-third-countries-a-study-of-bangladesh-and-myanmar.

20. भारत सरकार , विदेश मंत्रालय. "लाइन्स ऑफ़ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स." *विदेश मंत्रालय.* 2024. https://www.mea.gov.in/Lines-of-Credit-for-Development-Projects.htm.

21. भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय. "नेशनल साइबर सिक्योरिटी पालिसी 2013." *इंडिया.जीओवी.इन नेशनल पोर्टल ऑफ़ इंडिया* . 2013 . https://www.india.gov.in/national-cyber-security-policy-2013.

22. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय. *एनुअल रिपोर्ट 2022-2023.* रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 2023.

23. भारद्वाज, संजय कुमार. "टेनेंट्स ऑफ़ इंडिया-बांग्लादेश रिलेशन्स." *इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल* (प्रिंट्स पुब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड ) 15, no. 3 (2020): 259-267.

24. —. *द चाइनीज शैडो ऑन इंडिया' स ईस्टवार्ड इंगेजमेंट.* Edited by संजय कुमार भारद्वाज. लंदन: रूटलेज, 2021.

25. भारद्वाज, संजय कुमार. "बांग्लादेश फॉरेन पालिसी विस्-ए-विस् इंडिया." *स्ट्रेटेजिक एनालिसिस* (टेलर फ्रांसिस ऑनलाइन ) 27, no. 2 (2003): 263-278.

26. मजूमदार, महमुदुल हक़. "मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द बे ऑफ़ बंगाल: ए बांग्लादेश पर्सपेक्टिव." *बांग्लादेश इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज जर्नल* 44, no. 2 (2023): 161-185.

27. मतिअस , दप्पे हर्रेरा, मथिल्डे लेब्रैंड, and डायना वन पेटन. "ब्रिजिंग बांग्लादेश एंड इंडिया क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड एंड द मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट." *वर्ल्ड बैंक.* 2021. https://documents1.worldbank.org/curated/en/635471616767281403/pdf/Bridging-Bangladesh-and-India-Cross-Border-Trade-and-the-Motor-Vehicles-Agreement.pdf.

28. मिनिस्ट्री ऑफ़ इनफार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग, गवर्मेंट ऑफ़ द पीपल'स रिपब्लिक बांग्लादेश. *प्रेस इनफार्मेशन डिपार्टमेंट* . 2023. https://pressinform.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pressinform.portal.gov.bd/allnotes/6ab3e0d8_18c8_48f3_b426_1aa6ae64828e/2023-04-25-05-31-5e2d00429aa194bebc9cdb83a45c7948.pdf.

29. मेगल, जहांजाइब, and मुहम्मद नदीम मिर्ज़ा. "स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स एंड नेकलेस ऑफ़ डायमंड्स: सिनो-इंडियन जिओ-स्ट्रेटेजिक कम्पटीशन इन द इंडियन ओसियन." *एशिया-पसिफ़िक एनुअल रिसर्च जर्नल ऑफ़ फार ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया* 40 (2022): 21-41.

30. रक्षा मंत्रालय. "इंडिया बांग्लादेश होल्ड द फिफ्थ एनुअल डिफेन्स डायलाग इन ढाका." *प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो.* 2023. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1952947.

31. राजू, कमोडोर महादेवु गोवेर्धन. "एन्हान्सिंग मेरीटाइम कोऑपरेशन अमोंग द लित्तोरल स्टेट्स इन द बे ऑफ़ बंगाल रीजन ( बीबीआर )." *एनडीसी इ जर्नल* 17, no. 1 (2018): 134-154.

32. वर्ल्ड इकनोमिक फोरम. "अक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी न्यू एविडेंस फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंसियल इंस्टीटूशन्स." *वर्ल्ड इकनोमिक फोरम.* 2014. https://www3.weforum.org/docs/WEF_AcceleratingInfrastructureDelivery_2014.pdf.

33. सज्जाद, मोहम्मद होसैन, मोहम्मद बिन अमीन, तमन्ना मरजान, मोहम्मद अतिकुर रहमान, and मसुक अब्दुल्लाह. "द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ऑफ़ चीन: ओप्पोर्तुनिटीज़ एंड चैलेंजेज फॉर बांग्लादेश इन साउथ एशियाई जिओ-स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट." *जर्नल ऑफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, पालिसी एंड डेवलपमेंट* 8, no. 11 (2024).

34. सलाम, मोहम्मद फखुस, मोहम्मद शकील भुइयां, and नूर ए जन्नत नीतू . "चीन'स एप्रोच टुवर्ड्स बांग्लादेश: डेवलपमेंट ऑफ़ पार्टनरशिप और क्लॉ ऑफ़ सबजुगतिओं?" *जर्नल ऑफ़ सोशल एंड पोलिटिकल साइंसेज* (द एशियाई इंस्टिट्यूट ऑफ़ रिसर्च) 3, no. 2 (2020): 465-473.

35. सूरी, कमोडोर गोपाल. "चाइनीज सबमरीन्स फॉर द बांग्लादेश नेवी: एन असेसमेंट." *विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन.* 2016. https://www.vifindia.org/article/2016/april/13/chinese-submarines-for-the-bangladesh-navy-an-assessment.

36. सेक्रेटेरिएट, सार्क. "चार्टर ऑफ़ द साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन." *बिम्सटेक.* मार्च 30, 2022. https://bimstec.org/charter?utm_source=chatgpt.com.

37. सैमुम, रूबियत. "बांग्लादेश'स स्ट्रेटेजिक पाइवोट टू द इंडो-पसिफ़िक." *ईस्ट एशिया फोरम.* जून 2023. https://eastasiaforum.org/2023/06/09/bangladeshs-strategic-pivot-to-the-indo-pacific/.

38. हसन, ए. "बांग्लादेश'स हेजिंग फॉरेन रिलेशन्स: द दिलेम्स ऑफ़ ए वीक स्टेट." *एशिया टुडे एंड अफ्रीका,* no. 4 (2024): 39-46.